

केरल लोकायुक्त की शक्तियों में कमी

प्रलिस के लयः

लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त अधनियम, 2013 ।

मेन्स के लयः

लोकपाल और लोकायुक्त अधनियम, 2013, द्वतीय प्रशासनक सुधार आयोग, लोकपाल की कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दे तथा समाधान, भ्रष्टाचार वरिधी उपाय ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा केरल लोकायुक्त अधनियम, 1999 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया, जिसकी वपिकष द्वारा आलोचना की गई है ।

- प्रस्तावति अध्यादेश में भ्रष्टाचार वरिधी प्रहरी की शक्तियों को सीमति करने की परकिल्पना प्रस्तुत की गई है ।

प्रमुख बदि

प्रस्तावति परविरतनः

- केरल कैबनित ने राज्यपाल से सफारशि की है कविह अध्यादेश जारी करे ।
- इस प्रस्ताव में लोकायुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद सरकार को उसके नरिणय को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति देने की मांग की गई ।
- इस अध्यादेश से अरद्ध-न्यायकि संस्था एक दंतवहीन सलाहकार नकिय (Toothless Advisory Body) में परविरतति हो जाएगी जिसके आदेश सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगे ।

लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणाः

- [लोकपाल तथा लोकायुक्त अधनियम, 2013](#) ने संघ (केंद्र) के लयि लोकपाल और राज्यों के लयि लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की ।
- ये संस्थाएँ बनिा कसिी संवैधानक दरजे वाले वैधानक नकिय हैं ।
- ओम्बड्समैन या लोकपाल का कार्य कुछ नश्चिति श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के वरिद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करना है ।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधनियम, 2013 लोकपाल की स्थापना का प्रावधान करता है । लोकपाल संस्था का चेरपरसन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदग्धि सत्यनषिठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ती होना चाहिये ।
 - आठ अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायकि सदस्य तथा कम-से -कम 50 प्रतशित सदस्य अनु. जात/अनु. जनजात/अन्य पछिड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिये ।
 - लोकपाल की नयिकता वरष 2019 में की गई थी और इसने मार्च 2020 से कार्य करना शुरू कर दिया था । वर्तमान लोकायुक्त सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश **पनिकी चंद्र घोष** हैं ।
 - लोकपाल के पास कसिी ऐसे व्यक्ती के खलिाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का अधिकार है जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी. और डी. अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं ।
 - इसके कषेत्राधिकार में वह व्यक्ती भी शामिल है जो ऐसे कसिी नकिय/समति का प्रभारी (नदिशक/प्रबंधक/सचवि) है या रहा है जो केंद्रीय कानून द्वारा स्थापति हो या कसिी अन्य संस्था का प्रभारी जो केंद्रीय सरकार द्वारा वतितपोषति/नयित्तरति हो ।
 - इसमें कसिी ऐसे समाज या ट्रस्ट या नकिय को भी शामिल किया गया है जो 10 लाख रुपए से अधिक का वदिशी योगदान प्राप्त करता है ।

भारत में लोकपाल (Ombudsman) की ऐतहिसकि पृष्ठभूमि क्या है?

- लोकपाल यानी Ombudsman संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन में हुई।
- 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बड्समैन का विकास हुआ और **द्वितीय विश्व युद्ध** के बाद इसके विकास में तेज़ी आई।
- गुयाना प्रथम विकासशील देश था, जिसने वर्ष 1966 में ओम्बड्समैन का विचार अपनाया। इसके बाद मॉरीशस, सिंगापुर, मलेशिया के साथ-साथ भारत ने भी इसे अपनाया।
- **भारत में संवैधानिक ओम्बड्समैन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन** ने संसद में प्रस्तुत किया था।
- लोकपाल और लोकायुक्त शब्द डॉ. एल. एम. सघिवी द्वारा गढ़े गए थे।
- वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सांसदों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के निवारण हेतु केंद्रीय और राज्य स्तर पर दो स्वतंत्र प्राधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की।
- वर्ष 1968 में लोकपाल विधायक लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह व्यपगत हो गया और तब से यह कई बार लोकसभा में व्यपगत हो चुका है।
- वर्ष 2002 में 'एम.एन. वेंकटचलैया' की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की समीक्षा हेतु गठित आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की; यह भी सिफारिश की कि प्रधानमंत्री को प्राधिकरण के दायरे से बाहर रखा जाए।
- वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल का कार्यालय जल्द-से-जल्द स्थापित किया जाना चाहिए।
- इसके लिये वर्ष 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में सामाजिक आंदोलन 'इंडिया अगैस्ट करप्शन मूवमेंट' ने तत्कालीन केंद्र सरकार पर दबाव डाला और परिणामस्वरूप लोकपाल एवं लोकायुक्त विधायक, 2013 पारित हुआ।

राज्यों में लोकायुक्त किस प्रकार कार्य करता है?

- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 63 में कहा गया है कि 'प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त नामक एक निकाय स्थापित किया जाएगा, यद्यपि अब तक ऐसा कोई निकाय राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त नहीं किया गया है।'
- इस निकाय को अधिनियम के लागू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर गठित किया जाएगा और यह मुख्य तौर पर सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का निपटान करेगा।
 - हालाँकि यह कानून मात्र एक फ्रेमवर्क है, इसकी विशिष्टताओं को तय करने के लिये राज्यों पर छोड़ दिया गया है।
 - यह देखते हुए कि राज्यों को अपने स्वयं के कानून बनाने की स्वायत्तता है, लोकायुक्त की शक्तियाँ विभिन्न पहलुओं पर अलग-अलग होती हैं, जैसे- कार्यकाल और अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिये मंजूरी की आवश्यकता।
- जब वर्ष 2013 में यह अधिनियम पारित किया गया था, तब पहले से ही मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में लोकायुक्त काम कर रहे थे एवं अत्यधिक सक्रिय थे।
 - अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अधिकांश राज्यों ने अब एक लोकायुक्त की स्थापना की है।

आगे की राह

- भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल हमारी राजनीतिक, कानूनी, प्रशासनिक और न्यायिक प्रणालियों में व्यापक सुधार के माध्यम से की जा सकती है।
- एक प्रभावी लोकपाल संस्था की स्थापना ऐसा ही एक उपाय है।
- इसी तरह लोकपाल की तरफ पर राज्यों में सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों और राज्य नगमों के दायरे में लोकायुक्तों की स्थापना की जानी चाहिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस